

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं० 2018/00230 (119/2018)

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री निराणाराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसल
टिब्बी जिला हनुमानगढ़। — अपीलान्त

बनाम

1. सुनीता पत्नी श्री सरजीत जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पवन कुमार पुत्र श्री सरजीत नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुनीता पत्नी श्री सरजीत जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स/प्रार्थीगण

3. जगदीश पुत्र श्री निराणाराम जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। — तरतीबी रेस्पोंडेंट/अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर, टिब्बी दिनांक 23.03.2018 प्रकरण संख्या

27/2017 बअनवानी सुनीता आदि बनाम महेन्द्र आदि

श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त।

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं० 1 व 2

श्री राजेन्द्र कुमार बेनीवाला रेस्पोंडेंट सं० 3 की और से

निर्णय

दिनांक — 22.02.2021


1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेंट/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के साथ एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि 654 आर.डी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज है। प्रार्थीया घर के पेटवारा के

Law
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तहत प्रार्थना-पत्र में वर्णितानुसार अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी अपने कब्जा काशत की कृषि भूमि का खाता अलग कायम कवाने व रकमराज अलग कायम करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि में दखलंदाजी करने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीया को अपूर्णाय क्षति होगी। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध खाता विभाजन करवाये बिना प्रार्थीया के कब्जा काशत व स्वामित्व की कृषि भूमि के विशिष्ट किलों पर अपना कब्जा नहीं करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीया के पति सरजीत से उनकी खरीद की हुई भूमि है, जिसपर अप्रार्थीगण का कब्जा काशत है। वह स्थगन प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। चक 654 आरडी खाता संख्या 56/159 के 219/315 (57) किला नं. 16, 17, 18 कुल 0.759 है० भूमि के संबंध में एक वाद माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय हनुमानगढ़ में विचाराधीन है जिसमें दोनों पक्षों की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।


2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश गलत, अपूर्ण, विधि विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। चक 654 आरडी के खाता संख्या 159/64 व वर्तमान खाता संख्या 56/159 की 0.759 है० भूमि का विक्रय अनुबंध रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 के पति /पिता सरजीत ने अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 21.10.2010 को निष्पादित किया जिस और उसी दिन विक्रय अनुबंध की अनुपालना में मौके पर कब्जा संभला दिया था तभी से भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काशत चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराने के उपरान्त भी




 राज्य अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़

इस पर कोई गौर नहीं किया है। वादाधीन कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं विक्रय अनुबंध एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या -2 अनुमानगढ़ द्वारा जारी स्थगन आदेश एवं विचाराधीन सिविल वाद व प्रार्थना-पत्र की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तु कर दी थी जिनका पर कोई गौर नहीं किया गया। रेस्पोजेण्ट को विक्रय अनुबंध का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अनुबंध की पालना बाबत अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.05.2017 को रेस्पोजेण्ट सं० 1 व 2 को नोटिस भेजे थे जो दिनांक 13.05.2017 को प्राप्त हुआ। इस नोटिस प्राप्त होने के बाद रेस्पोजेण्ट ने अनुबंध की पालना से बचने के लिए असदभावनापूर्वक तथ्यों को छुपाते हुए नोटिस प्राप्ति के तीन दिन बाद दिनांक 16.05.2017 को धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोजेण्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है मातहत अदालत से तथ्यों को छुपाया है। प्रार्थना-पत्र में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्ण्य क्षति के तीनों बिन्दुओं पर कोई विश्लेषण नहीं किया है। आदेश में कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है। फर्द अहकाम विरोधाभाषी है। प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 745, आरआरडी 2002 पेज 383, आबीजे 1999 पेज 344 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक 654 आर.डी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज है। प्रार्थीया घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थना-पत्र में वर्णितानुसार अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी अपने कब्जा काशत की कृषि भूमि खाता अलग कायम कवाने व रकमराज अलग कायम करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि में दखलंदाजी करने पर आमामादा है इस कारण प्रार्थीया को अपूर्ण्य क्षति होगी। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध खाता विभाजन करवाये बिना प्रार्थीया के कब्जा काशत व स्वामित्व


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़



की कृषि भूमि के विशिष्ट किलों पर अपना कब्जा नहीं करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था जो स्वीकार किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काशत है। प्रश्नगत इकरारनामा में किला नंबर का खुलासा नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान वकूलाय की बहस पर मनन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सुनीता द्वारा धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था, जिसमें अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थीगण के हक हिस्से की 1/3 हिस्सा आराजी के कब्जा कास्त में दखलअंदाजी न करने के आदेश दिये थे। तत्पश्चात् दिनांक 23.03.2018 को आदेशिका में यह अंकित किया है कि उभयपक्ष द्वारा बहस समायत की जा चुकी है एवं विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.05.2017 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया है। इस न्यायालय के मतानुसार अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा विचाराधीन है। उभयपक्ष के हक हिस्सों का निर्धारण वाद में तय होना है, इस बीच यदि वादग्रस्त आराजी की मौका की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उभयपक्ष के मध्य वाद बहुतलता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश को कन्फर्म किया है उसमें किसी प्रकार की विधि त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2018 यथावत रखा जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 22.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



Caris
22/2/21
(करतारसिंह पूनीया)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़